[Shri Arjun Sethi]

field is changed by the application of more water and fertiliser, the threat to yield caused by the triple alliance of weeds, pests and pathogens could become serious. Countering the risk effectively will be particularly important for the small farmers who cannot otherwise be expected to show an interest in making requisite investments in inputs which are vital to the success of high-yielding varieties programme.

Most important perhaps is the correction of yield disparities between regions. In rice yields, Punjab leads with 2,961 kilograms per hectares followed by Haryana. The average per hectare yield is 952 kilograms in Assam, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, which account for 66.8 per cent of the land under paddy against the national average of 1308 kilograms.

It is imperative on the part of the Government to rectify the distortions that exist in agriculture and take steps to increase production of rice.

**(v) Policy in regard to prices of agricultural products**

**श्री रामलाल राही** (मिसरिख) : सभापति महोदय, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों अथवा अन्य प्रकार की, मूल्य वृद्धि का सिलसिला हर चीज में इस देश में इस प्रकार प्रारम्भ हुआ जिसे किसी प्रकार भी रोक पाना सम्भव नहीं हो सका। साढ़े तीन दशकों में देखा जाए तो हर वस्तु का मूल्य कृषि क्षेत्र के उत्पादन में दस गुना से लेकर 20 गुना तक तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 20 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ा है। हमारे देश में हर तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन के मूल्य आम तौर पर बढ़ते हैं, पर किसान द्वारा उत्पादित अनाज और जायद फसलों के दाम हमेशा उस समय गिर जाते हैं जब किसान की फसलें पक कर खेत से घर आना शुरू होती हैं। परन्तु उसके घर से जब अनाज और जायद फसलें बिककर सरकारी भण्डारों अथवा निजि व्यवसायों के गोदामों में भर जाती हैं और उपभोक्ता के रूप में किसान तथा आदमी को पुनः उन्हें खरीदना पड़ता है तो फसल के समय की कीमत से ड्योढ़ी-दूनी रों की चुकाने पर वही चीजें उसे पुनः मिल पाती हैं। मई साल के तौर पर गत नवम्बर-दिसम्बर, 1983 में जहां थोक भाव में गेहूं प्रति कुन्टल 225 रु०, चना 225 रु० से 400 रु० प्रति कुन्टल, जो 142 रु० से 150 रु० प्रति कुन्टल, सरसों 500 रु० से 600 रु० प्रति कुन्टल, अरहर लगभग 500 रु० प्रति कुन्टल थी। वही अब जब किसान के खेत में पक कर तैयार हुई और घर से बाजार तक पहुंचने की नौबत आई तो गेहूं के दाम गिरकर 150 रु० से 170 रु० प्रति कुन्टल, चना 275 रु० से 300 रुपए प्रति कुन्टल, जौ 100 से 110 रु० प्रति कुन्टल, सरसों 400 रु० प्रति कुन्टल, अरहर 300 रु० प्रति कुन्टल किसान के घर से बिकना प्रारम्भ हो गई है। इसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन में किसान की जरूरत की वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, कृषि यन्त्र, बिजली, पानी खाद, सीमेंट ईंट, लोहा, कपड़ा आदि सभी वस्तुओं के दाम नवम्बर-दिसम्बर, सन् 1983 के बाद 5 से 10 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

इस देश का असंगठित किसान बराबर लुट रहा है। सरकार पर भी मात्र संगठित वर्गों का दबाव है। इसलिए किसान की आबादी का सरकार पर कोई असर भी नहीं। देश की अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन जहां औद्योगिक उत्पादन पर होता है, वहीं कृषि प्रधान देश में उसके मूल्यांकन का प्रमुख महत्व कृषि उत्पादन पर है। परन्तु किसान की उपेक्षा उसे हताश किये है। सरकार से मांग है कि किसान के साथ न्याय किया जाए। समय-समय पर फसलों पर किसान के उत्पादित अनाजों और जायद फसलों के किस प्रकार मूल्य घटे-बढ़े हैं, उसी दर से औद्योगिक उत्पादों जैसे कपड़ा, लोहा, ट्रैक्टर, डीजल, ईंट सीमेन्ट आदि किसान और आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम भी घटने-बढ़ने चाहिए। आशा है सरकार देश की 80 परसेन्ट किसानों की लूट को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।